भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3248

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2026 को दिया जाना है ।

29 फाल्गुन, 1947 (शक)

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, 2026 के परिणाम

3248. श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान, विशेष रूप से नैतिक शासन में वैश्विक दक्षिण की भागीदारी के संदर्भ में, हासिल किए गए प्रमुख परिणाम और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ क्या-क्या हैं;
(ख) एआई इम्पैक्ट एक्सपो में जनसंख्या-स्तरीय समाधान प्रस्तुत करने में सफल स्वदेशी स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की कुल संख्या कितनी है और इन घरेलू नवोन्मेषकों के लिए उत्पन्न निवेश के अवसरों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) इंडिया एआई कंप्यूट क्षमता स्तंभ की वर्तमान स्थिति क्या है, विशेष रूप से 10,000+ जीपीयू क्लस्टर के पूर्ण संचालन की समय-सीमा और टियर-2 एवं टियर-3 शहरों के शोधकर्ताओं को सब्सिडी वाले कंप्यूट की सुलभता प्रदान करने के लिए कौन सा तंत्र स्थापित किया गया है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग) माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग का लोकतंत्रीकरण कर रही है। वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने और अंततः नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

भारत सरकार एआई के जिम्मेदार और समावेशी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारों, उद्योग, शिक्षाविदों और राज्यों के साथ मिलकर काम करती है।

भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026

वैश्विक एआई इकोसिस्टम में भारत की बढ़ती भूमिका को देखते हुए, भारत ने पेरिस एआई एक्शन समिट 2025 की सह-अध्यक्षता की। इस गति को आगे बढ़ाते हुए, भारत ने 16-21 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को होस्ट किया।

यह अब तक का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन था और ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला शिखर सम्मेलन था। यह बदलाव एक अधिक समावेशी वैश्विक एआई संवाद की ओर एक व्यापक कदम का संकेत देता है।

यह शिखर सम्मेलन ने सरकारों, उद्योग, शिक्षाविदों, नागरिक समाज और स्टार्टअप के नेताओं को एक मंच पर एक साथ लाया। इसमें 22 राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों सहित 100 से अधिक देशों और लगभग 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया।

शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित प्रमुख पहल और परिणाम:

- शिखर सम्मेलन के दौरान सात विषयगत कार्य समूहों द्वारा किए गए कार्यों को स्वीकार करते हुए घोषणा के साथ 92 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट घोषणा का समर्थन किया गया

- नई दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट प्रतिबद्धताओं पर 13 प्रमुख मॉडल प्रदाताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए
- प्रत्येक डिलिवरेबल के लिए 20+ देशों के व्यक्तिगत समर्थन के साथ 7 कार्य समूहों में 12 डिलिवरेबल्स [पिछले शिखर सम्मेलनों की तुलना में काफी अधिक]
    - 30+ देशों में 80+ इम्पैक्ट स्टोरीज़ के साथ ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स का शुभारंभ
    - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के साथ साझेदारी में इक्विटेबल एआई ट्रांजिशन प्लेबुक का विमोचन
    - लचीले, अभिनव और कुशल एआई के लिए स्वैच्छिक मार्गदर्शक सिद्धांतों पर हस्ताक्षर, 20+ देशों द्वारा समर्थन किया गया
    - एआई के युग में रीस्किलिंग के लिए स्वैच्छिक मार्गदर्शक सिद्धांतों पर हस्ताक्षर, 24 देशों द्वारा समर्थित
    - 25 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन से एआई के लोकतांत्रिक प्रसार के लिए चार्टर को अपनाना
    - लचीले एआई बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए प्लेबुक का विमोचन
    - एआई गवर्नेंस पर मार्गदर्शन नोट जारी करना, 22 देशों द्वारा समर्थित
    - औपचारिक लॉन्च से पहले 23 भागीदार देशों के साथ विश्वसनीय एआई कॉमन्स की घोषणा
    - एआई के माध्यम से समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन की घोषणा की गई, 21 देशों और यूनिसेफ द्वारा इसका समर्थन किया गया
    - शुरुआत में 20 भागीदार देशों के साथ विज्ञान संस्थानों के लिए एआई नेटवर्क का शुभारंभ
    - फ्रांस और यूनेस्को के साथ साझेदारी में रेजिलिएंट एआई चैलेंज का शुभारंभ
- एआई उत्तरदायित्व अभियान - वैश्विक रिकॉर्ड: भारत ने 2.5 लाख से अधिक मान्य प्रतिज्ञाओं के साथ "24 घंटे में एआई जिम्मेदारी अभियान के लिए प्राप्त सबसे अधिक प्रतिज्ञाओं" के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सफलतापूर्वक हासिल किया
- उच्च प्रभाव वाले एआई परिनियोजन का दस्तावेजीकरण करने वाली छह वैश्विक केसबुक जारी की गईं, जिनमें शामिल हैं:
    - स्वास्थ्य में एआई (डब्ल्यूएचओ के साथ)
    - ऊर्जा में एआई (आईईए के साथ)
    - लैंगिक सशक्तिकरण में एआई (संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ)
    - कृषि में एआई (महाराष्ट्र सरकार के साथ, विश्व बैंक द्वारा समर्थित)
    - शिक्षा में एआई (सीएसएफ और एकस्टेप फाउंडेशन के साथ)
    - एक्सेसिबिलिटी में एआई (एलिम्को, आईआईआईटी-बैंगलोर और चेंजइंक फाउंडेशन के साथ)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक भी लॉन्च की गई, जो भारत के एआई और डीप-टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम में अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करती है।

शिखर सम्मेलन में एआई मूल्य श्रृंखला में निवेश प्रतिबद्धताओं की घोषणाएं भी हुईं, जिसमें बुनियादी ढांचे, फाउंडेशन मॉडल, हार्डवेयर और अनुप्रयोगों में 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के अपेक्षित निवेश शामिल हैं।

वैश्विक उद्यम पूंजी फर्मों ने एआई नवाचार का समर्थन करने के लिए बहु-अरब डॉलर के निवेश का वादा किया, जबकि एक अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनी ने कनेक्टिविटी, भारत में एक एआई हब और लाखों लोक सेवकों और छात्रों तक पहुंचने वाले बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण पहल में महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की।

<u>पैक्स सिलिका</u>

भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हुआ। गठबंधन में संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य भागीदार देश शामिल हैं और वैश्विक सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने और एक लचीले प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का आयोजन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के एक भाग के रूप में किया गया था। कॉरपोरेट्स, स्टार्टअप, देश के प्रतिनिधित्व, केंद्र सरकार (न्यूनतम और विभाग), राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शिक्षाविदों/अनुसंधान संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों ने इसमें भाग लिया।

प्रदर्शकों के रूप में कुल 908 संगठनों ने भाग लिया। प्रतिभागियों की सूची वेबसाइट https://www.impactexpo.indiaai.gov.in/ पर उपलब्ध है।

इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो में प्रदर्शकों का श्रेणी-वार विवरण इस प्रकार है:

प्रदर्शक श्रेणी	**संख्या**
कॉरपोरेट्स	192
स्टार्टअप	611
देश के मंडप	13
केंद्र सरकार (मंत्रालय और विभाग)	26
राज्य सरकार	21
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	10
शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान	29
गैर सरकारी संगठन	6
कुल योग	**908**

एआई नेतृत्व के लिए भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण:

सरकार ने मार्च 2024 में **इंडियाएआई मिशन** को मंजूरी दी । इसे एक व्यापक, समावेशी और टिकाऊ एआई पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रयास के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

इंडियाएआई कंप्यूट

सरकार एआई में नवाचार के लिए कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व को पहचानती है। जैसे-जैसे भारत वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए एआई का उपयोग करने और एआई मॉडल विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, डेवलपर्स को प्रशिक्षण और अनुमान दोनों के लिए बड़े पैमाने पर गणना तक पहुंच की आवश्यकता होती है।

इंडियाएआई मिशन के तहत कॉमन कंप्यूट स्टार्टअप, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी संगठनों को हाई-एंड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर तक सस्ती पहुंच प्रदान करता है।

- साझा एआई कंप्यूट बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 14 एआई सेवा प्रदाताओं के माध्यम से 38,000 से अधिक जीपीयू को सूचीबद्ध किया गया है
- मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा और जामनगर सहित देश भर में स्थित डेटा सेंटर ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं
- इंडियाएआई कंप्यूट पोर्टल (https://compute.indiaai.gov.in) शोधकर्ताओं सहित योग्य उपयोगकर्ताओं को जीपीयू कंप्यूट संसाधनों को खोजने और उन तक पहुंचने में सक्षम बनाता है
- औसत गणना लागत लगभग 65 रुपये है, जो वैश्विक औसत लागत का एक तिहाई है

इंडियाएआई मिशन के तहत 20,000 जीपीयू जोड़कर गणना क्षमता का और विस्तार किया जा रहा है(वर्तमान में प्रक्रिया में) ।

*****